

जनजातियों के विकास की शासकीय योजनाओं के प्रति सहरिया जनजाति की जागरूकता एवं उन पर इन योजनाओं का प्रभाव

किशना राम चौधरी*
अरुणा कौशिक**
सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ***

जनगणना, 2011 के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास बहुत असमान है। इसमें राजस्थान की सहरिया जनजाति सबसे अधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है, यह राज्य में केवल बारों ज़िले के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में ही मुख्य रूप से निवास करती है। इनके निवास स्थान सुदूर वन-क्षेत्रों, बंजर तथा पथरीली भूमि में स्थित हैं। आज भी यह जनजाति एक आदिम समाज की भाँति जीवनयापन कर रही है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के संदर्भ में जनजातियों के शैक्षणिक विकास से संबंधित संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभावों के शोध के परिणामों से अवगत कराना है। यह अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों समकों पर आधारित है। जिसमें प्रतिदर्श का आकार 200 सहरिया परिवारों का है। इन परिवारों का यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से चयन करके गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से प्रश्नावली तथा प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से समकों का संकलन किया गया। सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का सहरिया बाहुल्य तहसीलों— किशनगंज तथा शाहाबाद में तुलनात्मक प्रदर्शन का विश्लेषण अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष पाया गया है कि सहरिया जनजाति शैक्षणिक विकास के लिए संचालित 12 अलग-अलग प्रकार की योजनाओं माँ-बाड़ी केंद्र, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, निःशुल्क स्टेशनरी वितरण, निःशुल्क पोशाक वितरण, निःशुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण, सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उपस्थिति प्रोत्साहन में से प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित चार तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए संचालित दो योजनाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों तथा सहरिया छात्राओं के लिए संचालित शेष छह योजनाएँ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। सहरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पर बहुत सीमा तक शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

*असिस्टेंट प्रोफ़ेसर (अर्थशास्त्र), कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021

**प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारों, राजस्थान 325 205

***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर (अर्थशास्त्र), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021

‘जनजाति’ शब्द का अर्थ ऐसे समाज या समाज के उस हिस्से से है जिसके सदस्य सामान्य तौर पर रीति-रिवाज, विश्वास और नेतृत्व आदि के संदर्भ में एक ही वंश से संबंधित होते हैं। अन्य शब्दों में, जनजाति को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि एकसमान व्यवसाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। संसार की अधिकांश जनजातियाँ वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये वन क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनकी आजीविका वन उत्पादों तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। अपनी घुमंतू प्रवृत्ति के चलते इनमें से अधिकांश जनजातियाँ एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमती रहती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे आदिवासी समुदायों के लिए ‘अनुसूचित जनजाति’ शब्द का प्रयोग संवैधानिक रूप से किया गया है।

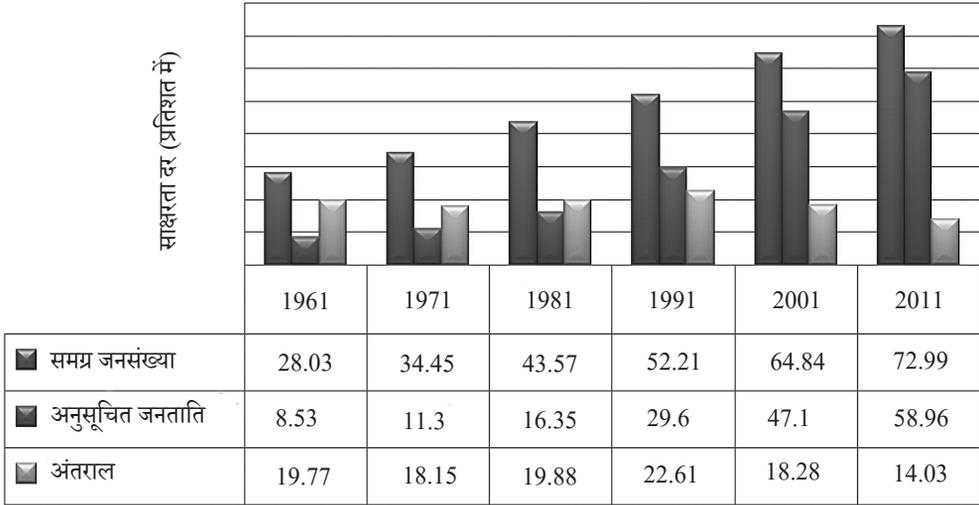
संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारत में सात सौ से अधिक आदिवासी समुदायों को ‘अनुसूचित जनजाति’ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें से कुछ समुदाय आदिम ढंग की विशेषताओं वाले हैं। इन आदिम समूहों में घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक पिछड़ेपन की विशेषताएँ विद्यमान हैं, ये सभी समूह आर्थिक रूप से

समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं। स्वतंत्रता के 74 वर्षों के उपरांत भी ऐसे आदिम समुदायों के अधिकांश लोग शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के पर्याप्त स्तर को हासिल नहीं कर पाए हैं और उनका स्वास्थ्य सूचकांक अत्यंत न्यून स्तर का बना हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान सहित 18 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में बसे हुए ऐसे 75 आदिम समुदायों की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (प्रीमिटिव वलनेरेबल ग्रुप्स—पी.वी.टी.जी.) की श्रेणी में रखा है। सहरिया आदिम समुदाय एक ऐसा ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में बसा हुआ है।

भारत में जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास बहुत असमान है। जनजातीय साक्षरता दर सघन जनजातीय आबादी के सर्केड्रण वाले राज्यों में अपेक्षाकृत बहुत ऊँची है, जैसे— मिज़ोरम (91.5 प्रतिशत), नागालैंड (80.0 प्रतिशत), मेघालय (74.5 प्रतिशत) तथा मणिपुर (72.6 प्रतिशत)। जबकि देश की अधिकांश जनजातीय आबादी वाले राज्यों का प्रदर्शन जनजातीय साक्षरता दर की दृष्टि से अपेक्षाकृत अत्यंत चिंताजनक है, जैसे — आंध्र प्रदेश (49.2 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (50.6 प्रतिशत), ओडिशा (52.2 प्रतिशत), राजस्थान (52.8 प्रतिशत) तथा झारखंड (57.1 प्रतिशत)। रेखाचित्र 1 तथा उसके संगत सारणी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पिछले छह दशकों के दौरान

रेखाचित्र 1— समग्र भारत तथा अनुसूचित जनजाति की तुलनात्मक साक्षरता दर



स्रोत— स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ़ शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013, सेक्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफ़ेयर्स, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ संख्या 13.
www.tribal.nic.in

समग्र भारत तथा जनजातीय साक्षरता दर की तुलना की जाए तो दोनों के मध्य पाया जाने वाला अंतराल बहुत अधिक है, परंतु पिछली तीन जनगणनाओं में इस अंतराल में आई गिरावट ने सरकारी प्रयासों की सफलता को सार्थक सिद्ध किया है।

सहरिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए जो प्रयास किए गए उनमें सहरिया जनजाति भी अछूती नहीं है। परंतु यह आदिम जनजाति देश के विशेष रूप से कमजोर समूहों में से एक है, जो इन सरकारी प्रयासों से अपनी अज्ञानता, निर्धनता, भोलेपन तथा शर्मिलेपन के चलते कम लाभ अर्जित कर पाई जबकि अन्य दूसरी जनजातियों ने प्रायः अधिक लाभ प्राप्त किया

है। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारत स्तर पर समग्र जनजातियों के लिए साक्षरता की दर 58.96 प्रतिशत है। जबकि सभी जनजातियों के लिए पुरुष तथा महिला साक्षरता की दर क्रमशः 68.53 प्रतिशत तथा 49.35 प्रतिशत है। सहरिया जनजाति की बसावट वाले राज्यों की राज्य स्तर पर समग्र जनजातियों तथा सहरिया साक्षरता दरों का तुलनात्मक विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1 से यह स्पष्ट होता है कि अपवाद स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में सहरिया आदिम जनजाति शैक्षणिक विकास की दृष्टि से अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक पिछड़ी हुई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सहरिया जनजाति

की बहुत कम आबादी बसी हुई है। जबकि इनकी 95 प्रतिशत से अधिक आबादी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में ही निवास करती है। राजस्थान में यह जनजाति केवल राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित बारों ज़िले की किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में बसी हुई है। यह राज्य की एकमात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) की श्रेणी वाली जनजाति है, जो समग्र विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ी हुई जनजाति मानी जाती है। इनके शैक्षणिक उत्थान के लिए राजस्थान में विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे— माँ-बाड़ी केंद्र, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, निःशुल्क स्टेशनरी वितरण, निःशुल्क पोशाक वितरण, निःशुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण, सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उपस्थिति प्रोत्साहन आदि।

उद्देश्य

यह शोध अध्ययन राजस्थान की सहरिया जनजाति पर आधारित है। इस शोध पत्र में इस जनजाति के शैक्षणिक

विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की भूमिका का किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2002 में राजस्थान की सहरिया जनजाति के वितरण के संबंध में माणक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा आयोजित सर्वे से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में सहरिया जनजाति की सघन बसावट केवल बारों ज़िले की इन्हीं दो तहसीलों में है। इन दोनों तहसीलों में प्रदेश की लगभग 92 प्रतिशत सहरिया आबादी बसी हुई है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न 12 शासकीय योजनाओं का इन दोनों तहसीलों के संदर्भ में निम्नलिखित आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना था—

- शासकीय योजनाओं के संबंध में सहरिया जनजाति के लोगों की जानकारी का अध्ययन करना।
- शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सहरिया परिवारों का अध्ययन करना।
- शासकीय योजनाओं से सहरिया जनजाति के लोगों के शिक्षा के स्तर, उनकी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

तालिका 1— राज्यवार साक्षरता दर (प्रतिशत में)

राज्य	समग्र अनुसूचित जनजातियाँ			सहरिया जनजाति		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
छत्तीसगढ़	69.7	48.8	59.1	90.8	68.3	80.9
राजस्थान	67.6	37.3	52.8	61.9	33.7	48.0
मध्य प्रदेश	59.6	41.5	50.6	51.7	32.0	42.1

स्रोत— स्टैटिस्टिकल प्रोफ़ाइल ऑफ़ शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013, सेक्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ संख्या 13 www.tribal.nic.in

साहित्य सिंहावलोकन

भारत में पिछड़े वर्गों— विशेषकर आदिवासी समुदायों के समुचित उत्थान के लिए अनेक प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए व किए जा रहे हैं। शोधार्थियों द्वारा समय-समय पर इन परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावों का विश्लेषण तथा आनुभविक अध्ययन किया गया। जैसा (2015) के अनुसार औपनिवेशिक काल में आदिवासी समूहों के लिए केवल सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के अलावा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने औपनिवेशिक काल की नीतियों में थोड़ा-सा संशोधन करके इन प्रयासों को जारी रखा तथा अनुसूचित जनजातियों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी सेवाओं में 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दीं। इन प्रावधानों ने जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कर दिया, परंतु इनकी शैक्षिक योग्यता तथा आवश्यक न्यूनतम कौशलों की कमी ने उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित रखा और अधिकतर मामलों में इनके लिए आरक्षित सीटें सदैव ही रिक्त रही हैं।

घोष (2007) ने अपने शोध पत्र में पश्चिम बंगाल की 'लोढ़ा' तथा झारखंड की 'हो' एवं 'महाली' जनजातियों में निम्न साक्षरता के कारणों की विस्तृत चर्चा करते हुए, यह बताने का प्रयास किया कि इन आदिवासी समुदायों में नामांकन अनुपात के संबंध में अपेक्षाकृत उच्च जेंडर विषमता व्याप्त है। दरीपा (2017) ने भारत में स्वतंत्रता

प्राप्ति के पश्चात् आदिवासी समुदायों की शैक्षणिक उन्नति के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों तथा उनके परिणामस्वरूप इन समुदायों में उत्पन्न शैक्षणिक माहौल का द्वितीयक समकों के आधार पर विश्लेषण किया। उन्होंने भारत के सभी समुदायों तथा आदिवासी समुदायों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया कि आज भी अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में वृद्धि तथा साक्षरता दर अपेक्षाकृत अत्यंत निम्न स्तर की है। गौतम (2013) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर विचार प्रकट करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा आदिवासी समुदायों का न केवल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह उनके समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में कार्य करता है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का मूल कारण निरक्षरता ही है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उनके शैक्षणिक मानकों में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। परंतु समग्र भारत में जनजातियों की निम्न साक्षरता दर की समस्या को बार-बार एकसमान नए-नए कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करके हल नहीं किया जा सकता है। बल्कि जनजातियों की न्यून साक्षरता दर समस्या को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग विशिष्ट कार्यक्रमों तथा योजनाओं को बनाकर ही हल किया जा सकता है।

शोध प्रविधि

यह शोध पत्र राजस्थान की सहरिया जनजाति पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है, जिसमें सहरिया जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित बारह अलग-अलग तरह की शैक्षणिक योजनाओं का किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया। राजस्थान की सहरिया बाहुल्य तहसीलों— किशनगंज तथा शाहाबाद में से प्रत्येक तहसील से पाँच-पाँच गाँवों का चयन स्तरित प्रतिचयन विधि के माध्यम से किया गया तथा प्रत्येक चयनित गाँव में से 20-20 परिवारों अर्थात् प्रत्येक तहसील से 100 परिवारों तथा कुल 200 परिवारों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया। इस प्रकार 200 परिवारों का प्रतिदर्श लेकर फ़रवरी, 2020 में 32 स्मार्टफ़ोन धारकों से गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नावली तथा शेष 168 सहरिया परिवारों से उनके क्षेत्रों में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से समकों का संकलन किया गया। प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण मापनी (स्केल), नामित (नॉमिनल) तथा क्रमिक (ऑर्डिनल) पैमाने के आधार पर किया गया। एकत्रित समकों की कमियों, अशुद्धियों तथा अनियमितताओं को यथोचित मात्रा में ठीक करते हुए उन्हें समानता तथा सजातीयता के आधार पर विभिन्न वर्गों तथा समूहों में वर्गीकृत करते हुए क्रॉस सारणीयन तथा रेखाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। समकों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया।

विश्लेषण

राजस्थान में सहरिया आदिम समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित

12 अलग-अलग तरह की योजनाओं को मोटे तौर पर तीन वर्गों— शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाओं को, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित योजनाओं तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित योजनाओं आदि में वर्गीकृत किया गया। इन सभी योजनाओं का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान सरकार के निर्देशन में सहरिया परियोजना अधिकारी, शाहाबाद की देखरेख में किया जा रहा है। लक्षित उत्तरदाताओं से इन सभी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ के बारे में प्रश्न पूछने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं—

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के सहरिया क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास से संबंधित संचालित कुल चार योजनाओं में से पहली तीन— माँ-बाड़ी केंद्र, आश्रम छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय अत्यधिक चर्चित योजनाएँ हैं। इन तीनों योजनाओं के संचालन की जानकारी दोनों तहसीलों— किशनगंज तथा शाहाबाद की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को है। जबकि एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन की जानकारी किशनगंज (46 प्रतिशत) की अपेक्षा शाहाबाद (75 प्रतिशत) के सहरिया लोगों को अधिक है, इसका मुख्य कारण इस मॉडल स्कूल का शाहाबाद में स्थापित होना है। इन चारों योजनाओं में से दोनों तहसीलों में सबसे अधिक तथा सबसे कम चर्चित योजनाएँ क्रमशः माँ-बाड़ी केंद्र तथा एकलव्य मॉडल स्कूल हैं। जबकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित दोनों योजनाएँ— निःशुल्क स्टेनरी वितरण (कक्षा 1 से 5) तथा निःशुल्क पोशाक वितरण (कक्षा 1 से 5) दोनों

तालिका 2— सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाओं की स्थिति

योजनाएँ	किशनगंज (100)			शाहाबाद (100)				
	जानकारी		लाभान्वित	जानकारी		लाभान्वित		
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाएँ								
माँ-बाड़ी केंद्र	94	06	90	10	97	03	93	07
आश्रम छात्रावास	72	28	41	59	90	10	43	57
आवासीय विद्यालय	69	31	31	69	53	47	33	67
एकलव्य मॉडल स्कूल	46	54	06	94	75	25	08	92
प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित योजनाएँ (कक्षा 1 से 5)								
निःशुल्क स्टेशनरी वितरण	93	07	91	09	94	06	93	07
निःशुल्क पोशाक वितरण	93	07	91	09	94	06	93	07
माध्यामिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित योजनाएँ (कक्षा 6 से 12)								
निःशुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण	74	26	71	29	84	16	71	29
सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता	31	69	25	75	58	42	32	68
सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण	18	82	10	92	47	53	19	81
सहरिया छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण	18	82	06	94	36	64	01	99
प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	72	28	67	33	82	18	68	32
उपस्थिति प्रोत्साहन	73	27	67	33	83	17	69	31

ही तहसीलों में उत्कृष्ट स्तर पर प्रचलित हैं। इन योजनाओं के संचालन की जानकारी दोनों ही तहसीलों की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी को है। जहाँ एक ओर माध्यामिक स्तर (कक्षा 6 से 12) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित तीन योजनाओं— निःशुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन के बारे में किशनगंज तथा शाहाबाद के क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत से अधिक सहरिया जनजाति के लोग जानकारी रखते

हैं वहीं दूसरी ओर इस श्रेणी के अंतर्गत विशेष रूप से सहरिया जनजाति की छात्राओं के लिए संचालित तीन योजनाओं— सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि, निःशुल्क साइकिल (कक्षा 9–12) तथा स्कूटी के वितरण की जानकारी के संबंध में दोनों तहसीलों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है क्योंकि इन तीनों योजनाओं के बारे में किशनगंज तहसील के क्रमशः 31 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत और शाहाबाद तहसील के क्रमशः 58 प्रतिशत, 47 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत सहरिया लोग जागरूक

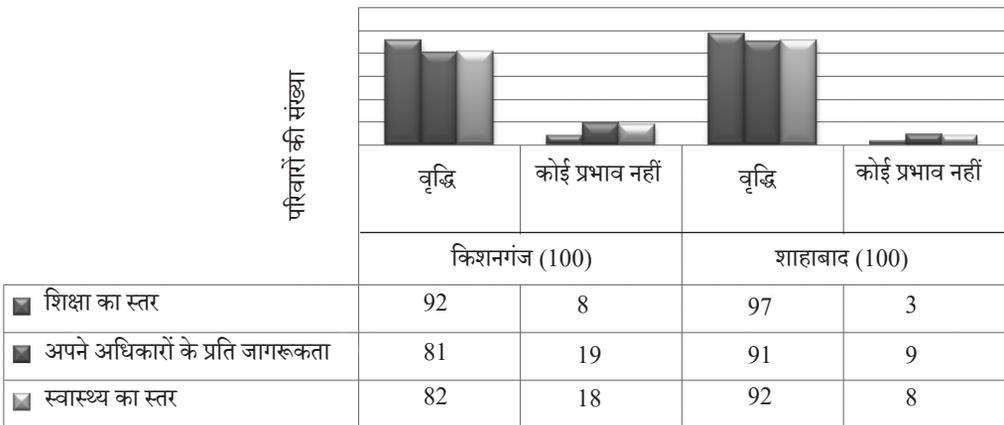
हैं। इस प्रकार तालिका 2 का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि माध्यामिक स्तर (कक्षा 6-12) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने के संबंध में शाहाबाद की स्थिति किशनगंज की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर है।

योजनाओं से लाभान्वित

योजनावार लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से दोनों तहसीलों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि शैक्षणिक विकास की तालिका 2 में दी गई 12 योजनाओं का प्रदर्शन दोनों तहसीलों में अलग-अलग रहा है और इनसे लाभ अर्जित करने वाले लाभार्थियों की संख्या में भी पर्याप्त विषमताएँ विद्यमान हैं। तालिका 2 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि माँ-बाड़ी केंद्रों के संचालन, निःशुल्क स्टेशनरी तथा पोशाक वितरण (कक्षा 1-5 तक) की योजनाओं से 90 प्रतिशत से अधिक सहरिया परिवार लाभान्वित हुए हैं। जबकि दोनों तहसीलों के दो-तिहाई से अधिक सहरिया परिवार माध्यामिक स्तर

(कक्षा 6-12 तक) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित निःशुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ्रीस वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। जो यह सिद्ध करता है कि माध्यमिक स्तर की सभी छह योजनाएँ अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रही हैं। इन योजनाओं की अपार सफलता का प्रमुख कारण साधारण लोगों तक इनकी पहुँच होना है, क्योंकि ये सभी योजनाएँ प्रत्येक गाँव तथा सहराना (सहरियों की बस्ती) के सरकारी स्कूलों तथा माँ-बाड़ी केंद्रों पर स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित की जा रही हैं। जबकि सहरियों की कमजोर आर्थिक स्थिति, योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता तथा मांग-पूर्ति के असंतुलन के चलते लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से उपर्युक्त योजनाओं के अलावा शेष बची छह योजनाओं का प्रदर्शन अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। जहाँ एक ओर इनमें से तीन योजनाओं—सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, आश्रम

रेखाचित्र 2— शैक्षणिक विकास की योजनाओं का सहरिया जनजाति पर प्रभाव



छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के संचालन के मामले में दोनों तहसीलों का प्रदर्शन औसत से कम है, क्योंकि इन तीनों योजनाओं से लाभ अर्जित करने वाले लाभार्थियों का अनुपात दोनों ही तहसीलों में 25 प्रतिशत से 43 प्रतिशत के मध्य है जो कि इन योजनाओं के असंतोषजनक प्रदर्शन को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इस दृष्टि से एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल (कक्षा 9-12) तथा स्कूटी के वितरण की योजनाओं के लाभार्थियों का दोनों तहसीलों में अनुपात 20 प्रतिशत से भी कम रहा है, इस प्रकार महिला शिक्षा के प्रति सहरियों की न्यून रुचि तथा पूरे क्षेत्र में केवल एक मॉडल स्कूल के संचालन के चलते दोनों ही तहसीलों में इन योजनाओं का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है।

योजनाओं का प्रभाव

सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत सहरिया जनजाति के शैक्षिक उत्थान हेतु संचालित शैक्षणिक विकास की 12 विभिन्न शासकीय योजनाओं के संदर्भ में चयनित प्रतिदर्श से उनकी शिक्षा के स्तर, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच-पड़ताल करने पर प्राप्त परिणामों को रेखाचित्र 2 तथा उसके संगत तालिका में दर्शाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सहरियों की शैक्षणिक विकास के लिए संचालित 12 अलग-अलग तरह की शासकीय योजनाओं का उनकी शिक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जहाँ एक ओर किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों के क्रमशः 92 प्रतिशत तथा 97 प्रतिशत

सहरिया जनजाति के परिवारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन योजनाओं के संचालन से उनकी शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के संचालन के परिणामस्वरूप अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में हुई वृद्धि की बात को किशनगंज तहसील के 81 प्रतिशत तथा शाहाबाद तहसील के 91 प्रतिशत सहरिया परिवारों ने स्वीकार किया है। इन योजनाओं से उनके स्वास्थ्य के स्तर में हुई वृद्धि की बात को किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों की क्रमशः 82 प्रतिशत तथा 92 प्रतिशत सहरिया आबादी ने स्वीकारा है।

इसके विपरीत दोनों ही तहसीलों के कुछ सहरिया परिवार ये मानते हैं कि सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत उनके शैक्षणिक विकास हेतु संचालित 12 योजनाओं में से अधिकतर योजनाएँ केवल प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों तक ही सीमित हैं। इसलिए किशनगंज क्षेत्र के 08, 19 एवं 18 प्रतिशत तथा शाहाबाद क्षेत्र के 03, 09 एवं 08 प्रतिशत सहरिया परिवार यह मानते हैं कि इन योजनाओं का क्रमशः उनकी शिक्षा के स्तर, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर में कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दिया है।

निष्कर्ष

राजस्थान की सहरिया जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्राथमिक समकों के आधार पर किए गए शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए माँ-बाड़ी केंद्रों का संचालन, निःशुल्क स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1-5), निःशुल्क पोशाक वितरण

(कक्षा 1-5), निःशुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण (कक्षा 6-12), प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन आदि छह योजनाओं का प्रदर्शन जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर का रहा है। इस प्रकार बारह में से छह योजनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन यह दर्शाता है कि सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। जबकि सहरियों के शैक्षणिक विकास की तीन अन्य योजनाओं— सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, आश्रम छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के संचालन का प्रदर्शन जानकारी के अनुपात की दृष्टि से तो सामान्य है, परंतु लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से असंतोषजनक है।

इन आश्रम छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, जैसे— भोजन, पेयजल, आवास तथा कठिन विषयों की अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा स्थानीय सहरियों से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि इन सुविधाओं में विशेषकर पेयजल तथा भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना अपेक्षित है। वहीं दूसरी ओर एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल (कक्षा 9-12) तथा स्कूटी के वितरण की योजनाओं का प्रदर्शन जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से अत्यंत ही निराशाजनक रहा है। इनमें से दो योजनाएँ सहरिया जनजाति की बालिकाओं के लिए संचालित हैं। अतः इन योजनाओं का कमजोर प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सहरियों की स्थिति अभी

भी अपेक्षाकृत रूप से अधिक कमजोर मानी जा सकती है। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

इन सभी योजनाओं की जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से क्रमशः आवासीय विद्यालयों के संचालन तथा सहरिया छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाओं में शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा बेहतर है। यही नहीं सहरियों के शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनाओं का उनके शिक्षा के स्तर, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर में हुई वृद्धि के मामले में भी शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है। इसका मुख्य कारण सहरिया विकास परियोजना से संबंधित अधिकतर सरकारी कार्यालय तथा संस्थानों की स्थापना शाहाबाद में होना है। अतः सहरिया विकास परियोजना से जुड़े नीति-निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भविष्य में सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए किशनगंज में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध पत्र में राजस्थान की सहरिया जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों के संदर्भ में किया गया है। शोध अध्ययन के निष्कर्षों से जहाँ एक ओर यह संतोषजनक परिणाम सामने आया कि सहरिया जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु संचालित 12 अलग-अलग योजनाओं

में से प्राथमिक स्तर (कक्षा 1- 4) की चार तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा 6- 12) की दो, इस प्रकार कुल छह योजनाओं का प्रदर्शन उत्तम श्रेणी का है। ये सभी योजनाएँ स्थानीय स्तर पर लक्षित वर्ग की जानकारी में हैं और अधिकतर सहरिया परिवार इनसे लाभान्वित हैं। वहीं दूसरी ओर लक्षित वर्ग की जानकारी तथा इनसे लाभान्वित परिवारों के अनुपात की दृष्टि से माध्यमिक स्तर (कक्षा 6-12) के विद्यार्थियों तथा सहरिया छात्राओं के लिए संचालित छह अन्य योजनाओं का प्रदर्शन अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। इन योजनाओं का सहरियों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पर बहुत सीमा तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यह एक संतोषजनक परिणाम है। इसके अतिरिक्त यदि इन योजनाओं का किशनगंज तथा शाहाबाद क्षेत्र के सहरियों में तुलनात्मक प्रदर्शन देखा जाए तो शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन 12 योजनाओं में से जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से क्रमशः आवासीय विद्यालयों के संचालन तथा सहरिया छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाओं में शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा बेहतर है। जोकि एक ओर शाहाबाद क्षेत्र के सहरियों के लिए एक हर्ष का विषय है तो दूसरी तरफ किशनगंज के सहरियों के लिए चिंता का विषय है।

शोध अध्ययन के निष्कर्षों से जहाँ एक ओर सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर इसके कमजोर पक्ष भी उजागर हुए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन कमजोर पक्षों को कैसे सुधारा जाए? सहरिया विकास परियोजना

से जुड़े जन-प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से भविष्य में यह आशा की जाती है कि वे सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित योजनाओं से सभी सहरियों को लाभान्वित करने का प्रयास करें।

सुझाव

राजस्थान में सहरिया आदिम समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन के संबंध में किए गए उपयुक्त तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें से अधिकतर योजनाओं का प्रदर्शन सहरिया छात्राओं तथा किशनगंज तहसील के सहरियों के लिए अपेक्षाकृत कमजोर रहा है जो इन योजनाओं के कमजोर पक्ष को उजागर करता है। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं को संशोधित कर वांछित लक्ष्यों को अर्जित करने योग्य बनाएँ तथा सहरिया छात्राओं और किशनगंज के सहरियों के शैक्षणिक विकास के संबंध में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का समुचित ढंग से समाधान किया जाए। इन बाधाओं के समुचित समाधानों के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

- योजनाओं का निर्माण सहरिया समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
- बालिका शिक्षा के प्रति सहरियों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास करने चाहिए।
- बालिका तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सुनियोजित ढंग से

प्रशिक्षित करके उन्हें स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अलग-अलग सुदूर तथा विषम भौगोलिक पारिस्थितिकी वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए।

- भविष्य में सहरिया विकास परियोजना से जुड़े नवीन शासकीय कार्यालयों की स्थापना किशनगंज क्षेत्र में की जाए।
- किशनगंज क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना करना और यहाँ पर पहले से संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा आश्रम छात्रावासों में आधुनिक सुविधाओं, जैसे— पुस्तकालयों, कक्षा-कक्षों, प्रयोगशालाओं तथा कंप्यूटर कक्षों आदि का पर्याप्त मात्रा में विस्तार किया जाना चाहिए।
- सुदूर वन तथा भौगोलिक विषमताओं वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन एवं विस्तार को बढ़ावा देना, ताकि वहाँ के वंचित लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके।
- किसी भी जनजाति अथवा वर्ग विशेष के सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपेक्षाकृत अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक रहता है। अतः किशनगंज क्षेत्र में बसने वाले सहरियों तथा सहरिया छात्राओं के मध्य

शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के प्रयास किए जाने चाहिए।

- किशनगंज क्षेत्र में सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शनियों, नुक्कड़ नाटकों, वीडियो शो तथा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास करने चाहिए।

इस प्रकार सहरिया जनजाति के लोगों को पर्याप्त स्तर तक जागरूक करने की आवश्यकता है। एक विचारक ने कहा था कि, 'ज्ञान ही सभी प्रकार की शक्तियाँ अर्जित करने का एकमात्र साधन है।' जानकारी को एक अदृश्य शक्ति माना जाता है, जिस व्यक्ति अथवा समूह के पास अपेक्षाकृत अधिक जानकारी उपलब्ध है, वही व्यक्ति अथवा समूह अधिक सक्षमता और सक्रियता से कार्य कर सकता है अर्थात् जहाँ की जनता जितनी अधिक जागरूक होगी। उसके विकास की संभावनाएँ उतनी ही प्रबल होंगी। जागरूकता का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्तिगत व सामूहिक विकास दोनों से ही है। अतः इन जनजातीय समूहों के शैक्षणिक उत्थान के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने के पर्याप्त प्रयास अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए।

संदर्भ

- गौतम, डॉ. एन. 2013. भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा— योजनाएँ तथा कार्यक्रम. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस*. वॉल्यूम IV, नंबर 04.
- घोष, ए. के. 2007. झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के मध्य साक्षरता तथा शिक्षा में लैंगिक अंतराल. *सोशियोलॉजिकल बुलेटिन*. वॉल्यूम XVI.

- जनजातीय कार्य मंत्रालय. *वार्षिक रिपोर्ट 2019–20*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.
- जैग्सा, वी. 2015. लेबर मार्केट एंड आदिवासिज—एन ओवरव्यू. *कांफ्रेंस सीरीज*. एस. आर. शंकरण चेरर. एन.आई.आर.डी., हैदराबाद.
- दरीपा, एस. एम. 2017. ट्राइबल एजुकेशन इन इण्डिया—गवर्मेंट इनिशिएटिव एंड चैलेंजेस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज*. वॉल्यूम VII, इशू 10, अक्टूबर, 2017.
- पटेल, एस. 1991. *ट्राइबल एजुकेशन इन इंडिया*. मित्तल पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
- प्राइमरी सेंसस एबस्ट्रैक्ट डाटा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. *जनगणना 2011*. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर, गवर्मेंट ऑफ इंडिया.
- मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. 2013. *स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया*. गवर्मेंट ऑफ इंडिया. www.tribal.nic.in
- सती, वी. पी. 2015. *सहरिया ट्राइब—सोसायटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड हैबिटेसन*, एनल्स ऑफ नेचुरल साइंसेज. वॉल्यूम I(1).